

भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
राज्यर सभा

अतारांकित प्रश्ना सं. 136 जिसका उत्तर
सोमवार, 30 नवंबर, 2015/9 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है

जलमार्गों का निर्माण

136. श्री नरेश अग्रवाल :

क्यार पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि सरकार की घोषणाओं के बावजूद जलमार्गों पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है;
- (ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं
- (ग) यदि नहीं, तो जलमार्गों के निर्माण की प्रगति की क्या स्थिति है और
- (घ) सरकार की जलमार्गों संबंधी क्या नीति है ?

उत्तर

पोत परिवहन राज्यर मंत्री
(श्री पोन्. राधाकृष्णबम्)

(क) से (घ) : इस देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूएनटी) को प्रोत्साहित करने के लिए, केन्द्रम सरकार ने अब तक निम्नेलिखित 05 अंतर्देशीय जलमार्गों की घोषणा राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यूएनटी) के रूप में की है:

- i) एनडब्ल्यूएनटी -1 के रूप में गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (इलाहाबाद-हल्द्वी कया - 1620 किमी)
- ii) एनडब्ल्यूएनटी -2 के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सदिया-891 किमी)
- iii) एनडब्ल्यूएनटी -3 के रूप में पश्चिम नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम) सहित उदयोगमंडल और चम्पारकारा नहरें (205 किमी)
- iv) एनडब्ल्यूएनटी -4 के रूप में काकीनाडा - पुडुचेरी नहरों सहित गोदावरी नदी और कृष्णा नदियां (1078 किमी)
- v) एनडब्ल्यूएनटी -5 के रूप में ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा नदियों के साथ एकीकृत पश्चिम तट नहर (588 किमी)

इन पांच राष्ट्रीय जलमार्गों में से, पहले तीन जलमार्गों को जरूरी गहराई और चौड़ाई का जलयान रास्ता, नौवहन सहायताएं और मार्गों की लदान/उतराई अथवा यात्रियों के

प्रवेश/निकासी के लिए टर्मिनल सुविधाएं पहले से ही काफी हद तक विकसित की गई हैं और इन राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो एवं यात्री जलयान संचलन कर रहे हैं। एनडब्ल्यू -1 की क्षमता वृद्धि के लिए वर्ल्ड बैंक सहायता प्राप्त परियोजना स्वीकृत हो गई है और लागू की जा रही है।

शेष रह गए दो राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास लंबित था क्यों कि योजना आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में इन जलमार्गों की घोषणा के उपरान्त सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से इन दो राष्ट्रीय जलमार्गों के वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य खंडों के विकास के लिए प्रयास किए गए थे। तथापि जब यह संभव नहीं पाया गया था, अब सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से यह विकास प्रक्रिया शुरू की गई है और कुछ एक परियोजनाएं लागू की जा रही हैं।

इसके साथ-साथ, यदि राष्ट्रीय जलमार्ग - 4 और 5 के कुछ खंडों का पीपीपी माध्यम से विकास किया जा सकता है, के आकलन का अध्ययन अंतिम स्तर पर है।

चैनल को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण, टर्मिनल सुविधाओं की स्थापना निकर्षण की गई सामग्री का ढेर बनाना आदि के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क करने के लिए और विभिन्न विकास आत्मलक्षित गतिविधियों की निगरानी किए जाने के लिए भी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय एनडब्ल्यू - 4 पर चेन्नैय एवं विजयवाडा और एनडब्ल्यू -5 पर भुवनेश्वर में खोले गए हैं।

राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में 101 और अंतर्देशीय जलमार्गों को घोषित करने के लिए, 2015 में संसद के बजट सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच के लिए भेजा गया। इस समिति और राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में 106 और अंतर्देशीय जलमार्गों को घोषित किए जाने के लिए मंत्रिमंडल के विचारार्थ एक नोट भेजा गया है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 के लिए "अधिकारिक संशोधन" प्रस्तुत किया जाएगा।
